

सं. घो. वि./रोहतक/7-85/1552.—धूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं शोहन त्पीतिंग मिल, रोहतक, ने अमिल श्री राज कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित भामले में कोई ग्रौटोग्राफिक विवाद है;

और धूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांडनीय समझते हैं;

इसलिए, श्रव, ग्रौटोग्राफिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्दर (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी ग्रधिसूचना सं. 3864-ए.एस.वि.(ह)।—श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा भामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिल के बीच या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित भामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित भामला है:—

या श्री राज कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 12 मार्च, 1985

सं. घो. वि./एफ.डी./9-85/9423.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है जो मैं श्रमोका आईस एफ.डी.नरल मिल, रिवाजी रोड, नारनोल के अमिल श्री गुरदियाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित भामले में कोई ग्रौटोग्राफिक विवाद है ;

और धूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांडनीय समझते हैं ;

इसलिये, श्रव, ग्रौटोग्राफिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्दर (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए ग्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा भामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिल के बीच या तो विवादग्रस्त भामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित भामला है :—

या श्री गुरदियाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. घो.वि./फरीदाबाद/2-85/9446.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं आटो ग्लाइड प्रा. ० लि. प्लाट नं. 64, सैकटर-6, फरीदा बाद, के अमिल श्री बहादुर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित भामले में कोई ग्रौटोग्राफिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांडनीय समझते हैं ;

इसलिये, श्रव, ग्रौटोग्राफिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्दर (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए ग्रधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा भामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिल के बीच या तो विवादग्रस्त भामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित भामला है :—

या श्री बहादुर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. घो.वि./फरीदाबाद/2-85/9453.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं आटो ग्लाइड प्रा. ० लि. प्लाट नं. 64, सैकटर 6, फरीदाबाद के अमिल श्री महेन्द्र सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिपित भामले में कोई ग्रौटोग्राफिक विवाद है ;

और धूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांडनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम 88-श्रम/57/1-245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी संबंधित मामला है :—

क्या श्री महेन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. श्रो. वि./एक.डी./35-85/9460.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै. जी. जी. टैक्सटाइल 22-ए, इण्डस्ट्रीजल एरिया, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री विभिषण तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/1-245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अधिकारी संबंधित मामला है :—

क्या श्री विभिषण की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 21 भार्च, 1985

सं. श्रो. वि./भिवा/गि/8-85/11541.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै. मोहन इलंकटो स्टील लि., अभानी, के श्रमिक श्री फतेह सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम 70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-प्रां. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री फतेह सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है

सं. श्रो. वि./रोहतक/234-84/11548.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मोहन स्वीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री रोहतास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रीद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-प्रां. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा

उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसमें सुनवाई नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय देते निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री रंगेन्द्र की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस गहरत का हृदयर है ?

सं. ओ. वि./रोहतक/231-84/11555.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मैं रोहत स्पीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई श्रोद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9041—श्रम-70/325, दिनांक 1 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3861-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1343, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुनवाई न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजेन्द्र प्रसाद की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

सं. ओ. वि./रोहतक/233-84/11562.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं संलग्न स्पीनिंग मिल, रोहतक, के श्रमिक श्री रामराजी नाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई श्रोद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641—श्रम/10/325/3, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित भरपूरी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस-ओ. (ई)-श्रम/70/1348, दिनांक 8 नवम्बर, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रामराजी नाल की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

दिनांक 4 मार्च, 1985

सं. ओ. वि./एफ.डी./8056.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं जीला इन्टर प्रासिज, प्लाट नं. 17, मार्किंट नं. 5, एन. आई.टी. फरीदाबाद के श्रमिक श्री पुनी तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद निवित मामले में कोई श्रोद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करता बांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, श्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-ब्र. 63/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11215, दिनांक 7 करवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उसके सुनवाई नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री पुनी की सेवाओं का समापन न्योनित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हृदयर है ?

प. प्रो.वि.कर्णोनाम: 11/2, 4-84/30 विवाह के राज्यान को राय है कि मे. डावरी वॉलस्टील एण्ड इन्जिनियरिंग क. वि. नाटन. 136, सैक्स ११ फरीदाबाद के अधिक थी नानक अन्दर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद विविध मानसे में कोई भी व्यापिक विवाद है :

प्रौढ़ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विराज ने न्यायितार्ग। हेतु निर्दिष्ट करता वांछनीय समझते हैं।

इसीपरे, प्रब्र, श्रीगंगिल विवाद प्रांतिका 1947, को धारा 10 को उपाय (1) के बाद (ग) द्वारा प्रदान को गई अधिकारी का प्रयोग करते हुए इसियां के राज्यान्तर इनके द्वारा सरकारी प्रविष्टियां सं. 5115-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जन, 1958, के साथ पहले दूसरे अधिकारी के द्वारा उक्त अधिकारी की धारा 7 के अधीन गठित श्रम व्यापारिय, फरारीवाद, को विवादप्रस्त या उससे मुंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला नामियंप हिन्दू निर्दिष्ट करते हैं जो कि उस प्रकारों तक प्रविष्टों के बोन या तो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से मुंगत व्यवासंगित रामता है।—

क्या धीरों नहीं की सेवाओं का समान व्यापोचित तथा श्रीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

म० श्रो. वि./रु. श० ३४-८५/८०७०.—वृक्ष हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि म० इण्डिया फोर्ज ए७३ ड्राफ्ट स्टेटिस्टिक वि०, १०/३, मधुरा रोड, फरीदाबाद के अधिक श्री मुरेश जर्मी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रांटिंग विवाद है ;

और वक्ति हुग्याण के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

उपरिए, अत्र, श्रीयोगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के छठे (ग) द्वारा प्रदान की गई अधिकारों का प्रयोग करने वाले हस्तियों के वाज्यपाल उस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1958, के माध्यम से द्वारा अधिकृत नं. 11493-श्रम-37/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उस अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अमन्यान्य, करीदाराएँ, को विवादपत्र या उससे सुसंगत या उससे यम्भवित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो यह उस प्रबन्धकों तथा अधिक के बीच या तो विवादपत्र मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।

क्या श्री मुरेश शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं० ओ. फि./एक. डा./103-84/8077.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० एन्सेन काटन मिल्ज, लिं०, मध्यराज्या रोड़ ब लवगढ़ के अधिक श्री मनी वन्सरी देवी तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई धीर्घांगिक विवाद है;

और वक्त हरियाणा के गज्यपाल निवास को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांठनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विद्याव अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के बाब्ड (ग) द्वारा प्राप्त की गई जमियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के गजपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम/१८/15254, दिनांक 20 जून, 1968, के माध्यम पढ़कर हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1968, द्वारा उक्त अधिनियम को धारा 1 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, करादावाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय को लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिक के बीच या नो विवादप्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है।--

क्या श्री मरो कुमारी देवी की मेराश्रो का गमाणन व्यापाच्चि । तथा ठीक है? परि नहीं, तो वह किस राहत की हूकदार है?

म. श्रोति/हि १२/२९-४-४/८१०५.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल ने राय है कि मैं इसार्थ संस्कृत नोआपरेटिव वैधि विव. हि १२, के अधिक श्री ओम प्रभास तथा उसने प्रबन्धमानों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मीठेगिक विवाद है;

प्रौर चुकि हरियांग के राज्यपाल निदान को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री ओम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./हिसार/76-84/8117.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं हरियाणा राज्य परिवहन, फिरसा, (2) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, के श्रमिक श्री राम प्रत-परिचालक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राम प्रत-परिचालक की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./हिसार/144-84/8124.—इरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं दो बैंक स्टाफ भर्ती अबैन (एम०ई०) थिफ्ट एण्ड क्रेडिट समिति लि., हिसार, के श्रमिक श्री राजीव चड्डा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए-एस.ओ. (ई) श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राजीव चड्डा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. ओ.वि./एफ.डी./31-85/8137.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं कोहिनूर पैन्ट्स प्रा. लि., 14/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री लल वहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत प्रथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री लल वहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?